जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

w w w .jaw abdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2024/kdgl/14 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 18 अक्तूबर 2024

नगर निगम जयपुर ग्रेटर के आग वाले महकमे मे भ्रष्टाचार बन रहा शिष्टाचार!!

फायर सेस की गणना मे हो रहा गड़बड़झाला!!!

फायर एनओसी की ऑनलाईन प्रक्रिया बन रही भ्रष्टाचार का जरिया!!

यह आग कब बुझेगी?

फायर एनओसी का रीन्युअल हो या फिर नई फायर एनओसी का आवेदन!!

50 हजार से 10 लाख तक का हो रहा खेल!!

आखिर कब पड़ेगी ACB की नजर?

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

नगर निगम ग्रेटर जयपुर के आग वाले महकमे मे भ्रष्टाचार बन रहा शिष्टाचार!!

पिछले कुछ सालों मे देश-प्रदेश मे आगजनी और अग्निकांड के कई बड़े मामले सामने आए है|ऐसे मामले सामने आने पर हमेशा की तरह रोना-पीटना मचता है,एक आध छोटे कर्मचारियों पर फौरी कार्यवाही कर दी जाती है और मामले समय के साथ रफा-दफा हो जाते है|सबसे बड़ी बात यह होती है कि ऐसी घटनाए हो जाने के बावजूद अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं की जाती|अग्निकांडों के कई बड़े मामलों मे तो संबंधित उपक्रम द्वारा विधिवत फायर एनओसी ही नहीं लेनी पाई गई है और कई मामलों मे यदि फायर एनओसी होती है तो अग्निशमन संबंधी उपकरण खराब मिलते है,संस्थानों के नियमित कर्मचारियों को फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती|इन सब मामलों के अलावा फायर एनओसी के खेल मे अब भ्रष्टचार का बड़ा खेल भी सामने आ रहा है|

फायर एनओसी की ऑनलाईन प्रक्रिया बन रही भ्रष्टाचार का जरिया!!

सूत्रों के अनुसार फायर एनओसी के खेल मे हो रहे भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए ही आवेदनों की ऑनलाईन प्रक्रिया शुरू की गई थी|लेकिन ऑनलाईन प्रक्रिया तो ऑफलाईन प्रक्रिया पर भी भारी पड़ती नजर आ रही है|सूत्रों के अनुसार जहां ऑफलाईन प्रक्रिया 7 चरणों मे हो रही थी वहीं अब ऑनलाईन प्रक्रिया 10 चरणों मे हो रही है|ऑफलाईन प्रक्रिया मे जहां फाईल एक बार फायर उपायुक्त के पास जाती थी वहीं अब ऑनलाईन प्रक्रिया मे एक आवेदक की फाईल चार बार फायर उपायुक्त के पास जा रही है|ऐसे मे आवेदक को चार बार कार्यालय मे धोक लगानी पड़ रही है और इसी खेल मे कोई ना कोई कमी निकालकर,आवेदक से मोटी रकम रिश्वत के तौर पर वसूल ली जाती है|

सूत्रों की माने तो बड़े बड़े संस्थानों मे फायर सेस की गणना मे भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है|एक प्राईवेट यूनिवर्सिटी के मामले मे तो करीब 66 लाख रुपये के फायर सेस को मोटी रिश्वत लेकर,महज 6 लाख रुपये मे सेटल कर दिया गया|ऐसे एक नहीं सैंकड़ों मामले है जिनकी ACB से जांच करवाई जाए तो ना केवल राजस्व को चुना लगाने के खेल का भंडाफोड़ हो सकता है बल्कि मोटी रिश्वत लेने वाले अधिकारियों के चेहरे भी सामने आने मे समय नहीं लगेगा|सूत्रों के अनुसार महकमे की बड़ी अधिकारी के कई किस्से भी चर्चित हो रहे है|उनपर बिना राज्य सरकार को इत्तला किए विदेश जाने के भी आरोप लग रहे है|सूत्रों की माने तो अधिकारी महोदया की रेट 50 हजार से लेकर 10 लाख रुपये तक है|

फायर एनओसी की ऑनलाईन प्रक्रिया मे हो रहे खेल को लेकर,अब फायर समिति के चेयरमेन पारस जैन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर प्रक्रिया को 10 चरणों की बजाय 6 चरणों मे करने का एक मसौदा प्रस्तुत किया है|देखना यह है कि अब इस बड़े मामले मे सरकार कुछ निर्णय लेती है या फिर आग का यह खेल ऐसे ही चलता रहेगा|